राज्य जरीये खुफिया अधिकारी, नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो

बनाम

मुश्ताक अहमद वगैरा

(आपराधिक अपील सं.1294-1295/ 2015)

6 अक्टूबर, 2015

[दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल सी. पंत, न्यायाधिपति]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, *1985* धारा *20(*बी*)(ii)(*सी*)* और धारा *2 (viia)* -मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ *(*संशोधन*)* अधिनियम, *2001 (2001* का अधिनियम संख्या *9)* - धारा *41 (1)* के वाणिज्यिक मात्रा की परिभाषा के भीतर जब्त प्रतिबंधित वस्तु - विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पहले प्रतिवादी और दूसरे प्रतिवादी के पास *6* किलोग्राम व *200* ग्राम एवं *4* किग्रा. क्रमशः चरस की और अभियोजन पक्ष इसे स्थापित करने में सक्षम था, प्रतिबंधित वस्तु को वाणिज्यिक मात्रा के रूप में माना और तदनुसार उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा *20 (*बी*) (ii) (*सी*)* के तहत दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को आरआई की सज़ा सुनाई - *12* वर्षों के लिए - हालांकि हाई कोर्ट ने माना कि आरोपी व्यक्तियों के कब्जे से बरामद की गई मादक दवा के एनडीपीएस अधिनियम की धारा *2(viia)* के संदर्भ में *"*मध्यवर्ती मात्रा*"* की थी सहपठित एस.ओ.*1055(*ई*)* दिनांक *19.1.2001* और *"*नोट *4"* के बाद *"*नोट *3"* जोड़ने से मामले का रंग नहीं बदला क्योंकि कथित वसूली पूर्व में *5.4.2004* को की गई थी- तदनुसार, उच्च न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा *8* सहपठित धारा *20(*बी*)(ii) (*बी*)* के तहत आरोपी-प्रतिवादियों की सज़ा को बदल दिया और हिरासत की अवधि को जो पहले ही गुजर चुकी अवधि तक सीमित कर दिया - अपील पर, माना गया*: 2001* के संशोधन अधिनियम

9 की धारा *41(1)* ने संशोधन प्रावधानों के आवेदन या बहिष्करण को निर्धारित किया - वर्तमान मामले में, घटना *2004* में हुई और, इसलिए, संशोधन *2001* का अधिनियम लागू- एनडीपीएस अधिनियम की धारा *2 (viia)* वाणिज्यिक मात्रा को परिभाषित करता है - विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि *19.10.2001* को ज़ारी अधिसूचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एक किलोग्राम से अधिक वाणिज्यिक मात्रा है - उच्च न्यायालय ने *"*टेट्रा-हाइड्रोकैनाबिनोल*"(*टी एच सी*)* सामग्री की उपस्थिति द्वारा निर्देशित वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित निष्कर्ष को उलट दिया -यह पाया गया कि जब्त किए गए समान में *50* ग्राम से अधिक टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल था दोनों आरोपी व्यक्तियों के संबंध में -- वर्तमान मामले में, जो प्रतिबंधित वस्तु जब्त की गई है वह *"*चरस*"* है - चरस और हशीश का रासायनिक नाम *"*कैनबिस का अर्क और टिंचर*"* है - इसका उल्लेख अधिसूचना प्रविष्टि संख्या *23* में मिलता है - अधिसूचना का क्रम संख्या *150* *"*टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल*"* से संबंधित है जिसकी एक लंबी सूची है - प्रतिबंधित वस्तु के लिए वाणिज्यिक मात्रा, अर्थात्, टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल *(*टीएचसी*)* जैसा कि प्रविष्टि संख्या *150* में बताया गया है *50* ग्राम है -यहां तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि उक्त प्रतिशत जब्त वस्तु में पाया जाता है तो भी प्रतिबंधित वस्तु *"*मध्यवर्ती*"* मात्रा से आगे निकल जाएगी और *"*वाणिज्यिक*"* मात्रा के अंतर्गत आ जाएगी - किसी भी स्कोर से आंका जाए तो उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार सही नहीं है - इसलिए, जब्त की गई वस्तु वाणिज्यिक मात्रा के अंतर्गत आती है और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा धारा *20 (*बी*) (ii) (*सी*)* के तहत दर्ज की गई दोषसिद्धि बिल्कुल त्रुटिहीन है - धारा *20(*बी*)(ii)(*सी*)* में कहा गया है कि न्यूनतम सज़ा दस साल होगी जिसे बीस साल तक बढ़ाया जा सकता है। तथ्यों पर, आरोपी-प्रतिवादियों को धारा *20(*बी*)(ii)(*सी*)* के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत और उनमें से प्रत्येक को दस साल के लिए आरआई *(कठोर कारावास)* से गुजरने और *1* लाख रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई।

सज़ा/सज़ा देना - न्यूनतम अनिवार्य सज़ा - प्रभाव - ठहराया: जब न्यूनतम सज़ा निर्धारित की जाती है, तो कोई भी अदालत कम सज़ा नहीं दे सकती।

नरेंद्र चंपकलाल त्रिवेदी बनाम गुजरात राज्य (2012) 7 एससीसी 80: 2012 (6) एससीआर 165; और मध्य प्रदेश राज्य बनाम अयूब खान (2012) 8 एससीसी 676: 2012 (7) एससीआर 427 - पर निर्भर किया।

अमर सिंह रामाजी भाई बारोट बनाम गुजरात राज्य (2005) 7 एससीसी 55; समीउल्लाह बनाम अधीक्षक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एआईआर 2009 एससी 1357: 2008 (15) एससीआर 626; ई. माइकल राज बनाम खुफिया अधिकारी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (2008) 5 एससीसी 161: 2008 (4) एससीआर 644; ओसेफ @ थंकाचन बनाम केरल राज्य (2004) 4 एससीसी 446; बशीर बनाम केरल राज्य (2004) 3 एससीसी 609: 2004 (2) एससीआर 224; हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) 4 एससीसी 441: 2011 (5) एससीआर 691 - संदर्भित।

<u>केस लॉज संदर्भ</u>

(2005) 7 एससीसी 55	संदर्भित	अनुच्छेद 3
2008 (15) एससीआर 626	संदर्भित	अनुच्छेद 3
2008 (4) एससीआर 644	संदर्भित	अनुच्छेद 3
(2004) 4 एससीसी 446	संदर्भित	अनुच्छेद 4

2004 (2) एससीआर 224	संदर्भित	अनुच्छेद 11
2011 (5) एससीआर 691	संदर्भित	अनुच्छेद 24
2012 (6) एससीआर 165	निर्भर किया	अनुच्छेद 27
2012 (7) एससीआर 427	निर्भर किया	अनुच्छेद 28

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1294-1295/2015

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू में दिनांक 03.06.2011 के निर्णय और आदेश से सीआरएल अपील संख्या 35 और 36/ 2009

एमएस.सुषमा मनचंदा, एम. खैराती, बी. कृष्णा प्रसाद, योशाक अध्यारू, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

सुश्री निधि, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया-

दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति।

1. इस अपील में, विशेष अनुमति द्वारा, जम्मू और कश्मीर राज्य ने आपराधिक अपील संख्या 35 और 36 /2009 में पारित निर्णय और आदेश के कानूनी औचित्य पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने इसे परिवर्तित कर दिया है विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा आरोपी उत्तरदाताओं को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षिप्तता के लिए, "एनडीपीएस अधिनियम") की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी मानते हुए सज़ा दर्ज की गई उनमें से प्रत्येक को

धारा 8 के तहत 12 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष से एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (बी) के साथ और हिरासत की अवधि को पहले से ही गुजरी अवधि तक सीमित कर दिया, यानी सात साल से थोड़ा अधिक और 25,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा - प्रत्येक एक संशोधित डिफ़ॉल्ट खंड के साथ।

2. जिन तथ्यों को बताया जाना आवश्यक है, वे यह हैं कि आरोपी-प्रतिवादियों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 सहपठित धारा 8 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था और तदनुसार, उन्हें मुकदमे के लिए भेजा गया था। आरोपी व्यक्तियों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए कई गवाहों से पूछताछ की और सबूत के तौर पर कई दस्तावेज पेश किए। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पहले प्रतिवादी मुश्ताक अहमद और दूसरे प्रतिवादी गुलजार अहमद के पास 6 किलोग्राम, 200 ग्राम एवं 4 किग्रा. क्रमशः चरस की थी और अभियोजन पक्ष इसे स्थापित करने में सक्षम था, प्रतिबंधित वस्तु को वाणिज्यिक मात्रा के रूप में माना और तदनुसार उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया और अंततः विचार किया अपराध की गंभीरता और नशीले पदार्थ समाज में बढ़ते और विनाशकारी खतरे को ध्यान में रखते हुए उन्मूलन की आवश्यकता पर , उनमें से प्रत्येक को सज़ा सुनाई गई जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है।

3. दोषसिद्धि के उपरोक्त फैसले और सज़ा के आदेश ने उत्तरदाताओं-अभियुक्तों को आपराधिक अपील संख्या 35 और 36 /2009 को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य किया और जम्मू में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दोनों अपीलों को एक

साथ सुना। खंड पीठ ने विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया और अमर सिंह रामाजी भाई बारोट बनाम गुजरात राज्य (2005) 7 एससीसी 55 और समीउल्लाह बनाम अधीक्षक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एआईआर 2009 एससी 1357 और माइकल राज बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (2008) 5 एससीसी 161 में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया। यह मानने के लिए कि आरोपी व्यक्तियों के कब्जे से बरामद की गई मादक ड्रग एस.ओ. 1055(ई) दिनांक 19.1.2001 सहपठित एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 (viia) के संदर्भ में "मध्यवर्ती मात्रा" की थी और "नोट 4" के बाद "नोट 3" जोड़ने से मामले का रंग नहीं बदला, क्योंकि कथित वसूली 5.4.2004 को की गई थी, यानी इससे भी अधिक संशोधन लागू होने से पांच साल पहले और इसके अलावा ऐसा कोई आरोप नहीं था कि बरामद पदार्थ में एक से अधिक मादक दवाएं या आइसोमर्स, एस्टर, ईथर और नशीली दवाओं के लवण पाए गए थे। इस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय ने राय दी कि आरोपी को केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (बी) सहपठित धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने तदनुसार, इस प्रकार ठहराया:-

> "38. उपरोक्त पृष्ठभूमि में अपीलकर्ताओं को अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (बी) सहपठित धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाना था और अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (बी)के तहत निर्धारित सज़ा दी जानी थी और न कि उन अपराधों के लिए निर्धारित सज़ा जिनमें अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत नशीली दवाओं की "व्यावसायिक मात्रा" का कब्ज़ा शामिल होना पाया जाता है। हालाँकि, अपीलकर्ताओं को 5.4.2004 को गिरफ्तार किया गया और वे पिछले सात वर्षों से अधिक समय से हिरासत में हैं।

39. इसलिए, हम अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (बी) में बदलते हैं और अपीलकर्ताओं को पहले से ही भुगते गए कारावास और 25000/ प्रत्येक को जुर्माने की सज़ा देते हैं। जुर्माने का भुगतान न करने पर अपीलकर्ताओं को छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा। आपराधिक अपील संख्या 35/2009 जिसका शीर्षक मुश्ताक अहमद बनाम राज्य और सीआर अपील संख्या 36/2009 शीर्षक गुलजार अहमद बनाम राज्य का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री सुषमा मनचंदा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को धारा 20(बी)(ii) (सी) से धारा 20(बी)(ii) (बी) में परिवर्तित करके गलती की है। एनडीपीएस अधिनियम में शब्दकोश के तहत "चरस" की परिभाषा पर विचार किए बिना अमर सिंह रामाजी भाई बारोट (सुप्रा), ओसेफ @ थंकाचन बनाम केरल राज्य (2004) 4 एससीसी 446 और ई. माइकल राज (सुप्रा) के निर्णयों पर भरोसा किया गया है एनडीपीएस अधिनियम की धारा और भ्रामक रूप से दूसरे पदार्थ पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसकी कोई प्रयोज्यता नहीं है। उन्होंने इस आधार पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की गंभीरता से आलोचना की है कि न तो परिभाषा और न ही प्रासंगिक अधिसूचना में दी गई शर्तें इस तरह के निष्कर्ष का समर्थन करती हैं और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कानून में असुरक्षित है।

5. प्रतिवादी की विद्वान वकील सुश्री निधि ने इसके विपरीत प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अपराध को एनडीपीएस अधिनियम धारा 20(बी)(ii) (सी) से धारा 20(बी)(ii)(बी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 8 में परिवर्तित कर दिया है जब्त की गई

प्रतिबंधित सामग्री में शामिल प्रतिशत के सम्बन्ध में और प्रावधान में निर्धारित सज़ा की ऊपरी सीमा में होने के कारण, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनका आगे यह कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्राधिकारों पर निर्भरता में दोष नहीं पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग को इस न्यायालय द्वारा अविवेकपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में नहीं माना जा सकता है।

6. हम पहले पहलू से पहले निपटेंगे, क्योंकि उस स्कोर पर हमारा निष्कर्ष अन्य प्रस्तुतियों को समाप्त कर देगा क्योंकि इसके लिए कोई वारंट नहीं होगा। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिबंधित सामग्री 5.4.2004 को जब्त की गई थी। उस समय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 इस प्रकार पढ़ी गईः-

> "8. कुछ कार्यों का निषेध - कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा-
>
> (ए) किसी भी कोका पौधे की खेती करना या कोका पौधे के किसी हिस्से को इकट्ठा करना; या
>
> (बी) अफ़ीम पोस्त या किसी भांग के पौधे की खेती करना; या
>
> (सी) उत्पादन, निर्माण, कब्ज़ा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, उपभोग, अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या किसी भी मादक पदार्थ या मनोदैहिक पदार्थ को स्थानांतरित करना,
>
> चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर और इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के प्रावधानों द्वारा प्रदान की गई तरीके और सीमा तक और ऐसे मामले में जहां ऐसा कोई प्रावधान,

लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के माध्यम से किसी भी आवश्यकता को लागू करता है।,ऐसे लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के अनुसार:

बशर्ते कि, और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन,गांजा के उत्पादन के लिए भांग के पौधे की खेती या चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्य के अलावा किसी भी लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, खरीद, बिक्री, परिवहन, भंडारण, अंतर-राज्य आयात और अंतर-राज्य निर्यात पर प्रतिबंध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है:

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात सजावटी प्रयोजनों के लिए पोस्ता भूसे के निर्यात पर लागू नहीं होगी।"

7. कुछ संशोधनों के बाद प्रासंगिक समय पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 इस प्रकार पढ़ें:-

"20. भांग के पौधे और भांग के संबंध में उल्लंघन के लिए सज़ा - जो कोई भी, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या दिए गए लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन करता है, -

(ए) किसी भांग के पौधे की खेती करता है; या

(बी) भांग का उत्पादन, विनिर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात या उपयोग करता है, दंडनीय होगा -

(i) जहां ऐसा उल्लंघन खंड (ए) से संबंधित है, उसे कठोर कारावास की सज़ा होगी, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है; और

(ii) जहां ऐसा उल्लंघन उप-खंड(बी)से संबंधित है-

(ए) और इसमें छोटी मात्रा शामिल है, एक अवधि के लिए कठोर कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ;

बी) और इसमें वाणिज्यिक मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से अधिक मात्रा शामिल है, जिसमें कठोर कारावास की सज़ा हो सकती है जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है;

(सी) और इसमें वाणिज्यिक मात्रा शामिल है, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे बीस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए कठोर कारावास होगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे दो लाख रुपये बढ़ाया जा सकता है :

बशर्ते कि अदालत, फैसले में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगा सकती है।"

8. संशोधन से पहले, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 इस प्रकार थी: -

"20. भांग के पौधे और भांग के संबंध में उल्लंघन के लिए सज़ा - जो कोई भी, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या दिए गए लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन करता है, -

(ए) किसी भांग के पौधे की खेती करता है; या

(बी) भांग का उत्पादन, विनिर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात या उपयोग करता है, दंडनीय होगा, -

(i) जहां ऐसा उल्लंघन गांजा या भांग के पौधे की खेती से संबंधित है, वहां कठोर कारावास की सज़ा होगी, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसे पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है;

(ii) जहां ऐसा उल्लंघन गांजे के अलावा अन्य भांग से संबंधित है, वहां कठोर कारावास की सज़ा हो सकती है जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे बीस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा और जिसे दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है:

बशर्ते कि अदालत, फैसले में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगा सकती है।"

9. विधायिका ने एनडीपीएस अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया, जो 2001 के अधिनियम 9 में संशोधन के माध्यम से 2.10.2001 को लागू हुआ। यह कहा गया है कि उक्त अधिनियम ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत सज़ा की संरचना को तर्कसंगत बनाया है, जो कि मात्रा से जुड़ी श्रेणीबद्ध सज़ा प्रदान करता है मादक उत्पाद या मन:प्रभावी पदार्थ जिसके संबंध में अपराध किया गया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार आशय की घोषणा करता है:-

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण

2001 का संशोधन अधिनियम 9.-स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 मादक द्रव्यों और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए निवारक दंड प्रदान करता है। अधिकांश अपराधों में न्यूनतम दस वर्ष के कठोर कारावास की एक समान सज़ा होती है जिसे बीस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जबकि अधिनियम में नशीली दवाओं के तस्करों के लिए कड़ी सज़ा की परिकल्पना की गई है, यह नशे की लत के आदी के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है। मुकदमे में सामान्य देरी को देखते हुए यह पाया गया है कि नशे की लत वाले लोग अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करना पसंद करते हैं। अधिनियम के तहत सख्त जमानत प्रावधान उनकी परेशानी को और बढ़ाते हैं। इसलिए, सज़ा संरचना को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले नशीली दवाओं के

तस्करों को निवारक सज़ा दी जाए, नशे की लत वाले लोगों और कम गंभीर अपराध करने वालों को कम कठोर सज़ा से दंडित किया जाए। इसके लिए अधिनियम के तहत प्रदान की गई दंड संरचना को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। यह उन अपराधियों के लिए सख्त जमानत प्रावधानों के आवेदन को प्रतिबंधित करने का भी प्रस्ताव है जो गंभीर अपराधों में लिप्त हैं।"

10. 2001 के संशोधन अधिनियम 9 की धारा 41 (1) ने संशोधित प्रावधानों के आवेदन या बहिष्करण को निर्धारित किया। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:-

"41. लंबित मामलों पर इस अधिनियम का लागू होना- (1) धारा 1 की उपधारा (2) में किसी बात के बावजूद, इस अधिनियम के प्रारंभ में अदालतों के समक्ष लंबित या जांच के तहत सभी मामलों का निपटारा तदनुसार किया जाएगा इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के प्रावधानों के साथ और तदनुसार, कोई भी व्यक्ति मूल अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का दोषी पाया गया, जैसा कि यह इस तरह के प्रवर्तन से ठीक पहले था, उस सज़ा के लिए उत्तरदायी होगा जो उस सज़ा से कम है जिसके लिए वह ऐसे अपराध के घटित होने की तिथि पर अन्यथा उत्तरदायी है:

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात अपील में लंबित मामलों पर लागू नहीं होगी।"

11. उक्त प्रावधान की संवैधानिक वैधता के संबंध में प्रश्न इसलिए उठा, क्योंकि मुकदमे का सामना कर रहे अभियुक्तों और उन दोषियों के बीच एक वर्गीकरण था, जिन्हें पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था और उनकी अपीलें 2.10.2001 के बाद लंबित थीं।

बशीर बनाम केरल राज्य (2004) 3 एससीसी 609 में इस न्यायालय ने वर्गीकरण से संबंधित कुछ प्राधिकारियों का उल्लेख करने के बाद इस प्रकार निष्कर्ष निकाला: -

"परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि 2001 के संशोधित अधिनियम 9 की धारा 41(1) का प्रावधान संवैधानिक है और अनुच्छेद 14 से प्रभावित नहीं है। नतीजतन, सभी मामलों में, जिनमें मुकदमाें में निष्कर्ष निकले थे और अपीलें 2-10-2001 पर लंबित थीं, जब 2001 का संशोधन अधिनियम 9 लागू हुआ, तो 2001 के संशोधन अधिनियम 9 द्वारा पेश किए गए संशोधन लागू नहीं होंगे और उन्हें एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार निपटाया जाना होगा, जैसा कि 2-10-2001 से पहले 1985 था।"

12. वर्तमान मामले में, माना जाता है कि घटना 2004 में हुई थी और इसलिए, 2001 अधिनियम लागू होता है। बाद की तारीख में संशोधन के माध्यम से शामिल किए गए 'नोट्स' पर इस मामले में बहस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुद्ध कारण के लिए उक्त नोट्स को वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्कोर के संबंध में आकर्षित नहीं किया जाएगा। वर्तमान में, हम एनडीपीएस अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करेंगे। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 (vii ए) वाणिज्यिक मात्रा को परिभाषित करती है। यह इस प्रकार है:-

> "2. (vii ए) "वाणिज्यिक मात्रा", नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक मात्रा का मतलब है;"

13. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 (xxiii ए) छोटी मात्रा को परिभाषित करती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"2. (xxiii ए) मादक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में "छोटी मात्रा" का अर्थ है आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से कम कोई भी मात्रा;"

14. इस समय, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2(iii) में निहित कैनबिस (गांजा) की परिभाषा का उल्लेख करना उचित है: -

"(ए) चरस, यानी, भांग के पौधे से प्राप्त अलग किया हुआ राल, किसी भी रूप में, चाहे वह कच्चा हो या शुद्ध, और इसमें सांद्रित तैयार पदार्थ और राल भी शामिल है जिसे हशीश तेल या तरल हशीश के रूप में जाना जाता है;

(बी) गांजा, यानी, कैनबिस पौधे के फूल या फलने वाले शीर्ष (बीज और पत्तियों को छोड़कर जब शीर्ष के साथ नहीं होते हैं), चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना या निर्दिष्ट किया जा सकता है; और

(सी) उपरोक्त किसी भी प्रकार की भांग या उससे तैयार किए गए किसी भी पेय का कोई भी मिश्रण, किसी तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना;" [जोर दिया गया]

15. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 के खंड (vii ए) और (xxiii ए) के तहत ज़ारी 19 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना से प्रासंगिक उद्धरण को पुन: प्रस्तुत करना उचित है। तालिका का अपेक्षित भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

एस आई. नं.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ का नाम	रासायनिक नाम	छोटी मात्रा (ग्राम	वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम/

	पदार्थ का नाम [अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम (आईएनएन)	[अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम (आईएनएन)		में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	कैनबिस और कैनबिस राल	चरस, हशीश	कैनिबस के अर्क और टिंचरस	100	1 कि. ग्रा.
150	टेट्राहाइड्रोकैनाबेबीनोल		निम्नलिखित आइसोमर्स और उनके स्टीरियोकेमिकल वेरिएंट: - 7,8,9,10- टेट्राहाइड्रो 6,6,9 ट्राइमेथिल-3- पेंटाइल-6 एच-डाईबेंज़ो [बी,डी] पाइरान 1-01 (9 आर. 10 एआर)- 8,9,10, 10 ए टेट्राहाइड्रो- 6,6,9- ट्राइमेथिल-3- पेंटाइल-6 एच-डाईबेंजो[बी,डी] पैरन-1-ol (6 ए आर, 9 आर, 10 ए आर)- 6 ए, 9,10,10a- टेट्राहाइड्रो- 6,6,9- ट्राइमेथिल-3- पेंटी 1-6H- डिबेंज़ो [बी,डी] पिरान-1-ओ एल (6 एआर, 10 एआर) 6 ए, 7, 10, 100 टेट्राहाइड्रो-6,6,9- ट्राइमेथिल-3-	2	50 ग्राम

			पेंटाइल 1-6 एच- डाईबेंज़ो [बी.डी पायरान-1-ओएल 68,7,8,9- टेट्राहाइड्रो- 6,6,9- ट्राइमेथिल-3- पेंटी-6 एच- डिबेंज़ो [बी,डी] पाइरान-4-ओएल (6 ए आर, 10 ए आर) 6 ए,7,8,9,10, 10 ए हेक्साहाइड्रो-6 6-डिमथाइल-1-9 मेथिलीन 3 पेंटाइल-6 एच- डिबेंज़ो [बी.डी पायरान-1-ओएल		

[ज़ोर दिया गया]

16. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने जब्त की गई प्रतिबंधित वस्तु को वाणिज्यिक मात्रा की परिभाषा के अंतर्गत माना था और तदनुसार आरोपी व्यक्तियों को दोषी पाया और सज़ा दी। उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि 19.10.2001 को ज़ारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि एक किलोग्राम से अधिक वाणिज्यिक मात्रा है। उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित निष्कर्ष को पलटते हुए इस प्रकार कहा है: -

> "यह इंगित करने की आवश्यकता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार रासायनिक परीक्षक ने न केवल यह पता लगाने के लिए नमूनों का विश्लेषण किया कि क्या इसमें कोई नारकोटिक ड्रग शामिल है या नहीं, बल्कि नारकोटिक ड्रग का नमूने में "वजन के अनुसार प्रतिशत" का पता लगाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गया। रासायनिक परीक्षक ने अपनी दिनांक 25.04.2004 की रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणित किया कि सात भूरे रंग की छड़ी के आकार के पदार्थों में से एक से लिए गए नमूने

में परिक्षण चरस के लिए सकारात्मक पाया गया और नमूने में टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल (टीएचसी) की मात्रा 5.1 प्रतिशत थी। अपीलकर्ता मुश्ताक अहमद टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल (टीएचसी) से बरामद पांच छड़ियों में से एक से उठाए गए नमूने के मामले में नमूने में सामग्री 5.1 प्रतिशत थी। अपीलकर्ता मुश्ताक अहमद टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल (टीएचसी) से बरामद पांच छड़ियों में से एक से उठाए गए नमूने में सामग्री 4.9 प्रतिशत पाई गई। इन परिस्थितियों में, यदि अपीलकर्ताओं से बरामद पदार्थ से उठाए गए नमूने क्रमशः 45 ग्राम और 39 ग्राम होंगे, तो प्रत्येक छड़ी का औसत वजन 890 (6.2 किलोग्राम-7) और 800 (4.0 किग्रा-5) ग्राम क्रमश: होगा। हालाँकि, यदि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई धारणा पर काम करते हुए कि अपीलकर्ताओं के इकबालिया बयानों के मद्देनजर, पूरे पदार्थ को प्रतिबंधित नमूने के बावजूद चरस के रूप में लिया जाना था, तो नारकोटिक अपीलकर्ताओं से बरामद पूरे पदार्थ में नारकोटिक तत्व अभी भी क्रमशः 316 ग्राम और 196 ग्राम होगी।"

17. हमने इस बात की सराहना करने के लिए उपरोक्त अनुच्छेद को पुन: प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय को "टेट्रा-हाइड्रोकैनाबिनोल" (टीएचसी) सामग्री की उपस्थिति द्वारा निर्देशित किया गया है और उस आधार पर यह मानने के लिए आगे बढ़ा है कि दोनों आरोपी व्यक्तियों से जब्त की गई वस्तु छोटी मात्रा से परे है लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम है। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, अनिवार्य रूप से ओसेफ @थैंकाचन (सुप्रा) और ई. माइकल राज (सुप्रा) पर निर्भरता रखी गई है।

18. हम उक्त निर्णयों के अनुपात का विश्लेषण करना उचित समझते हैं। ओसेफ @ थंकाचन (सुप्रा) में, आरोपी के पास ब्यूप्रेनोर्फिन के 110 एम्पौल्स पाए गए, जिसका व्यापार नाम टिडिगेसिक है। अदालत ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या मनोदैहिक पदार्थ कम मात्रा में था और यदि हां, तो क्या यह व्यक्तिगत उपभोग के लिए था। उस संबंध में, न्यायालय ने यह कहा:-

> "हमारे द्वारा विचार किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या मनोदैहिक पदार्थ कम मात्रा में था और यदि हां, तो क्या यह व्यक्तिगत उपभोग के लिए था। "छोटी मात्रा" शब्द को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 23-7-1996 की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। राज्य के विद्वान वकील ने हमारे ध्यान में लाया है कि उक्त अधिसूचना के अनुसार छोटी मात्रा को 1 ग्राम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यदि हां, तो अपीलकर्ता से बरामद मात्रा केंद्र सरकार द्वारा ज़ारी अधिसूचना में निर्दिष्ट छोटी मात्रा की सीमा से काफी कम है। यह माना गया है कि प्रत्येक एम्पुल में केवल 2 मिलीलीटर और प्रत्येक मिलीलीटर में केवल .3 मिलीग्राम होता है। इसका मतलब है कि अपीलकर्ता के कब्जे में पाई गई कुल मात्रा केवल 66 मिलीग्राम थी। यह अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट छोटी मात्रा की सीमा के 1/10 से भी कम है।"

19. ई. माइकल राज (सुप्रा) में, एक या अधिक तटस्थ पदार्थों के मिश्रण में स्वापक औषधि या मनोदैहिक पदार्थ के संबंध में एक छोटी या वाणिज्यिक मात्रा के निर्धारण से निपटने के दौरान दो-न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि तटस्थ पदार्थ की मात्रा को विचार में नहीं लिया जाना चाहिए और यह आपत्तिजनक दवा के वजन के आधार पर एकमात्र वास्तविक सामग्री है जो यह निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि

क्या यह छोटी मात्रा होगी या वाणिज्यिक मात्रा पर विचार किया जाना चाहिए। ई. माइकल राज (सुप्रा) में यह सवाल उठा कि अपीलकर्ताओं के कब्जे में पाया गया पदार्थ किस अधिसूचना की प्रविष्टि के तहत आएगा, यानी कि क्या प्रविष्टि 56 या प्रविष्टि 239। प्रविष्टियों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने निम्नानुसार माना :-

> "14. संशोधित अधिनियम के परिणामस्वरूप, दण्ड संरचना में भारी बदलाव आया। संशोधित अधिनियम ने पहली बार धारा 2 में खंड (vii-ए) जोड़कर मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में "वाणिज्यिक मात्रा" की अवधारणा पेश की, जो इस शब्द को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक किसी भी मात्रा के रूप में परिभाषित करता है। इसके अलावा, "छोटी मात्रा" शब्द को धारा 2 (xxiii-ए) में परिभाषित किया गया है, किसी भी कम मात्रा के रूप में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से। तर्कसंगत दण्ड संरचना के तहत, सज़ा इस बात पर निर्भर करती है कि गैर कानूनी सामग्री की मात्रा "छोटी मात्रा", "वाणिज्यिक मात्रा" या बीच में कुछ है।
>
> 15. 2001 के संशोधित अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा दण्ड संरचना को तर्कसंगत बनाना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नशीली दवाओं के तस्कर जो महत्वपूर्ण मात्रा में दवाओं की तस्करी करते हैं, उन्हें निवारक सज़ा से दंडित किया जाए, नशेड़ियों और कम गंभीर अपराध करने वालों को कम कठोर सज़ा दी जाती है। तर्कसंगत दण्ड संरचना के तहत, गैर कानूनी सामग्री की मात्रा के आधार पर सज़ा

अलग-अलग होगी। इस प्रकार, हमें प्रतिवादी की ओर से दिए गए तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि शुद्धता की दर अप्रासंगिक है क्योंकि कोई भी तैयारी जो 250 ग्राम की व्यावसायिक मात्रा से अधिक है और जिसमें 0.2% या अधिक हेरोइन है, धारा 21(सी) के तहत दंडनीय होगी। एनडीपीएस अधिनियम, क्योंकि विधायिका का इरादा जैसा कि हमें प्रतीत होता है, मिश्रण में आपत्तिजनक औषधि की सामग्री के आधार पर सज़ा देना है, न कि मिश्रण के वजन के आधार पर। इसका परीक्षण निम्नलिखित तर्क पर किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी आरोपी के पास से 4 ग्राम हेरोइन बरामद की जाती है, तो यह एक छोटी मात्रा होगी, लेकिन जब वही 4 ग्राम 50 किलोग्राम पाउडर चीनी के साथ मिलाया जाता है, तो इसे व्यावसायिक मात्रा के रूप में निर्धारित किया जाएगा। एक या एक से अधिक तटस्थ पदार्थ(ओं) के साथ एक मादक औषधि या एक मनोदैहिक पदार्थ के मिश्रण में, किसी मादक औषधि या मनोदैहिक पदार्थ की छोटी मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण करते समय तटस्थ पदार्थ(ओं) की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। यह केवल मादक पदार्थ के वजन के आधार पर वास्तविक सामग्री है जो यह निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है कि यह छोटी मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा होगी। जैसा कि हमें प्रतीत होता है, संशोधन पेश करने का विधायिका का इरादा कम गंभीर अपराध करने वाले लोगों को कम कठोर दंड से दंडित करना है और जो गंभीर अपराध करते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण मात्रा में तस्करी, उन्हें अधिक कठोर दंड देना है।"

20. उक्त मामले में, न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया कि हेरोइन की शुद्धता क्रमशः 1.4% और 1.6% थी और इसलिए, कब्जे में हेरोइन की मात्रा केवल 60 ग्राम थी और इस आधार पर इसे एक छोटी मात्रा के रूप में माना गया।

21. अमर सिंह रामाजी भाई बारोट (सुप्रा) में अपीलकर्ता को एक काला पैकेट ले जाते हुए पाया गया जिसमें काले रंग का तरल पदार्थ था जिसकी गंध अफीम जैसी थी। पुलिस पदाधिकारी ने उसके पास से बरामद उक्त पदार्थ का वजन किया तो वजन 920 ग्राम पाया गया. दूसरे आरोपी , जिसकी पहले ही मौत हो चुकी थी, के पास से 4.250 किलोग्राम ग्रे रंग का पदार्थ बरामद किया गया, जिसके मादक पदार्थ होने का संदेह था। अपीलकर्ता के पास से बरामद की गई 920 ग्राम अफ़ीम में से, नमूने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए थे, जिसमें कहा गया था कि जो पदार्थ भेजा गया था वह अफ़ीम था जिसमें 2.8% एनहाइड्राइड मॉर्फिन और पोस्ता के फूल (पोसेडोडा) के टुकड़े भी थे। दोनों आरोपी व्यक्तियों को मुकदमे का सामना करना पड़ा और विचारण न्यायालय ने दोनों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 17 और 18 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया और उनमें से प्रत्येक को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई डिफॉल्ट क्लॉज के साथ। अन्य अभियुक्त द्वारा की गई अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण समाप्त हो गई और अमरसिंह रामजीभाई बारोट की अपील खारिज कर दी गई। इस न्यायालय के समक्ष एक तर्क पेश किया गया था कि उच्च न्यायालय ने दो आरोपियों से संयुक्त रूप से बरामद आपत्तिजनक पदार्थ की कुल मात्रा लेकर गलती की थी और यह मानते हुए कि उक्त मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक थी, धारा 21(सी) एनडीपी अधिनियम के तहत सज़ा की मांग की गई थी। इस न्यायालय ने 920 ग्राम काले तरल के कब्जे के तथ्य और एफएसएल रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें बरामद पदार्थ अफ़ीम होने का संकेत दिया

गया था जिसमें 2.8% एनहाइड्राइड मॉर्फिन, इसके अलावा नमूने में पोस्ता (पोसेडोडा) के फूलों के टुकड़े भी पाए गए। न्यायालय ने धारा 2(xv) और 2(xvi) में अफ़ीम की परिभाषा का उल्लेख किया और इस प्रकार कहा:-

> 14. इस बात का कोई स्वीकार्य साक्ष्य प्रतीत नहीं होता है कि अपीलकर्ता के पास पाया गया काला पदार्थ "अफीम पोस्त का जमा हुआ रस" था और "अफीम पोस्त के जमे हुए रस का किसी तटस्थ पदार्थ के साथ या बिना कोई मिश्रण"। एफएसएल ने अपनी राय दी है कि यह "एनडीपीएस अधिनियम में वर्णित अफीम" है। यह अदालत पर बाध्यकारी नहीं है।
>
> 15. साक्ष्य यह भी नहीं दर्शाता है कि अपीलकर्ता से बरामद पदार्थ धारा 2(xvi) के उप-खंड (ए), (बी), (सी) या (डी) के अर्थ में आएगा। अवशिष्ट खंड (ई) 0.2 प्रतिशत से अधिक मॉर्फिन युक्त सभी तैयार सामग्री को अपने दायरे में ले लेगा। एफएसएल रिपोर्ट साबित करती है कि अपीलकर्ता के पास से बरामद पदार्थ में 2.8 प्रतिशत एनहाइड्राइड मॉर्फिन था। नतीजतन, यह धारा 2(xvi)(e) के अर्थ में "अफीम व्युत्पन्न" के समान होगा। धारा 2(xi) का खंड (ए) "निर्मित औषधि" अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित करता है:
>
> "2. (xi) 'निर्मित औषधि' का अर्थ है-
>
> (ए) सभी कोका डेरिवेटिव, औषधीय कैनबिस, अफ़ीम डेरिवेटिव और पोस्ता भूसे का सांद्रण;
>
> (बी)* * *”

सभी "अफीम व्युत्पन्न" एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2(xi) में परिभाषित "निर्मित औषधि" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलकर्ता से जो बरामद किया गया वह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2(xi) के अर्थ के तहत "निर्मित औषधि" थी। इसलिए, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री इंगित करती है कि अपीलकर्ता के खिलाफ साबित हुआ अपराध स्पष्ट रूप से "निर्मित औषधि" के अवैध कब्जे के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत आता है।

22. इस दृष्टिकोण से, यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत है कि यह एक वाणिज्यिक मात्रा थी। ई. माइकल राज (सुप्रा) में उक्त निर्णय को इस प्रकार प्रतिष्ठित किया गया है:-

"18. व्यथित होकर, अमरसिंह ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने फैसले के अनुच्छेद 14 में निम्नानुसार कहा है:

"14. इस बात का कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता के पास पाया गया काला पदार्थ 'अफीम पोस्त का जमा हुआ रस' था और 'किसी भी तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना, अफीम पोस्त के जमा हुए रस का कोई मिश्रण'। एफएसएल ने अपनी राय दी है कि यह 'एनडीपीएस अधिनियम में वर्णित अफीम' है। यह अदालत पर बाध्यकारी नहीं है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि साक्ष्य यह भी नहीं दर्शाता है कि अपीलकर्ता से बरामद पदार्थ धारा 2(xvi) के उप-खंड (ए), (बी), (सी) या (डी) के अर्थ में आएगा, लेकिन अवशिष्ट खंड (ई) लागू होगा और परिणामस्वरूप यह अफ़ीम व्युत्पन्न की श्रेणी में आएगा

क्योंकि सभी अफ़ीम व्युत्पन्न "निर्मित औषधियों" की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलकर्ता से जो बरामद किया गया था वह निर्मित औषधि थी और अपीलकर्ता के खिलाफ साबित हुआ अपराध स्पष्ट रूप से निर्मित औषधि के अवैध कब्जे के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत आता है। न्यायालय ने अनुच्छेद 17 में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला और कहा:

> "17. उक्त अधिसूचना में (क्रम संख्या 93 पर) अफीम डेरिवेटिव के संबंध में, 5 ग्राम को 'छोटी मात्रा' के रूप में और 250 ग्राम को 'वाणिज्यिक मात्रा' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सही था अपीलकर्ता निर्मित औषधि की 'व्यावसायिक मात्रा' को अवैध रूप से रखने का दोषी था। नतीजतन, उनका मामला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के खंड (सी) के तहत कवर किया जाएगा, न कि खंड (ए) या (बी) के तहत।"

इसलिए, इस अदालत ने धारा 21 (सी) के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की न्यूनतम सज़ा को बरकरार रखा है।

19. अमरसिंह मामले पर गौर करने पर हमें यह नहीं पता चला कि न्यायालय एक या अधिक तटस्थ पदार्थों के साथ एक मादक औषधि या मनोदैहिक पदार्थ के मिश्रण के सवाल पर विचार कर रहा था। वास्तव में न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा ही नहीं था। काले रंग के तरल पदार्थ को अफ़ीम व्युत्पन्न के रूप में लिया गया था और एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया था कि इसमें 2.8% एनहाइड्राइड मॉर्फिन था, जिसे केवल धारा 2 (xvi) (ई) के दायरे में लाने के उद्देश्य से माना गया था, अफ़ीम व्युत्पन्न" जिसके लिए न्यूनतम 0.2% मॉर्फिन की आवश्यकता होती है। 2.8% एनहाइड्राइड मॉर्फिन की पाई गई सामग्री को यह तय करने के प्रयोजनों के लिए बिल्कुल भी नहीं माना गया कि बरामद पदार्थ छोटी या

वाणिज्यिक मात्रा थी और न्यायालय ने पूरे पदार्थ को एक अफीम व्युत्पन्न के रूप में माना जो एक या अधिक तटस्थ पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं था। इस प्रकार, अमरसिंह मामले को प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए एक प्राधिकारी के रूप में नहीं लिया जा सकता है कि बरामद और जब्त किए गए पूरे पदार्थ को नशीली दवाओं या मनोदैहिक पदार्थ की सामग्री के बावजूद धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के आवेदन के लिए विचार किया सज़ा देने के उद्देश्य से। हमारा मानना है कि जब भी कोई मादक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ एक या एक से अधिक तटस्थ पदार्थों के साथ मिश्रित पाया जाता है, सज़ा देने के उद्देश्य से नशीले पदार्थ या मन:प्रभावी पदार्थ की सामग्री को ध्यान में रखा जाएगा।"

23. हमने उक्त निर्णय का उल्लेख किया है क्योंकि राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया था कि उक्त निर्णय वर्तमान मामले पर लागू होता है। हमारी सुविचारित राय में, उक्त मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स पूरी तरह से अलग था और वास्तव में, यह विनिर्माण और प्रतिशत सामग्री से निपट रहा था, इसलिए हमें इसमें गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है।

24. वर्तमान मामले में, ज़ब्त की गई प्रतिबंधित वस्तु "चरस" है और शब्दकोश खंड स्पष्ट रूप से बताता है यह कैनबिस से प्राप्त कच्चा या शुद्ध हो सकता है और इसमें सांद्रित तैयार सामग्री और राल भी शामिल है जिसे हशीश तेल या तरल हशीश के रूप में जाना जाता है। परिभाषा कोई भी भांग या उससे तैयार किए गए किसी भी पेय के किसी भी तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना कोई भी मिश्रण को भी इंगित करती है। धारा 2(iii) (सी) में संदर्भ किसी भी मिश्रण को संदर्भित करता है जिसमें आगे चरस का और संदर्भ होता है, जो कच्चा या शुद्ध बताता है। चरस और हशीश का रासायनिक नाम "अर्क

और टिंचर ऑफ कैनबिस" है। इसका उल्लेख अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 23 में मिलता है। अधिसूचना का क्रमांक 150 संबंधित है "टेट्राहाइड्रोकैनाबैबिनोल" से, एक लंबी सूची है।

25. उपरोक्त तथ्यात्मक स्कोर के संबंध में, हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) 4 एससीसी 441 में दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले का संदर्भ उपयुक्त होगा। उक्त प्रकरण में 7.10 कि.ग्रा. आरोपियों के पास से अफीम बंद कर दी गई। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा गया कि अपीलकर्ता के पास से बरामद अफीम का वजन 7.10 किलोग्राम था। इसमें 0.8% मॉर्फीन यानी 56.96 ग्राम थी और इसलिए, मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम थी। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने ई. माइकल राज (सुप्रा) में की गई घोषणा का उल्लेख किया और अधिसूचना में विभिन्न प्रविष्टियों का उल्लेख किया , जैसे, प्रविष्टि 77 जो मॉर्फिन से संबंधित है, प्रविष्टि 92 जो अफ़ीम से संबंधित है और प्रविष्टि 93 जो अफ़ीम डेरिवेटिव से संबंधित है। न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या मामला प्रविष्टि 92 या प्रविष्टि 93 या किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत आएगा। न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की परिभाषा का उल्लेख किया, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा किए गए रासायनिक विश्लेषण, मॉर्फिन के प्रतिशत पर ध्यान दिया, 2001 में लाया गया संशोधन और इस प्रकार लागू हुआ: -

> "21. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के पास से बरामद सामग्री अफीम थी। यह व्यावसायिक मात्रा में थी और अपीलकर्ता के व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं हो सकती थी। इस प्रकार अपीलकर्ता के पास प्रतिबंधित पदार्थ होने के कारण उसने प्रावधानों का उल्लंघन किया है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18(बी) के तहत उचित रूप से दोषी ठहराया गया था। तत्काल मामला स्पष्ट रूप से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2(xv) के खंड (ए) के

अंतर्गत आता है और इसका खंड (बी) लागू नहीं होता है इसका सीधा सा कारण यह है कि बरामद किया गया पदार्थ अफीम पोस्त के जमा हुए रस के रूप में था। यह किसी अन्य तटस्थ पदार्थ के साथ अफीम का मिश्रण नहीं था। उक्त जमा हुए रस से कोई नया पदार्थ बनाने की कोई तैयारी नहीं थी। सज़ा देने के उद्देश्य से यदि अफ़ीम में मॉर्फिन की मात्रा को निर्णायक कारक के रूप में लिया जाता है, तो प्रविष्टि 92 पूरी तरह से निरर्थक हो जाती है।

22. इस प्रकार, चूंकि मामला धारा 2(xv) के खंड (ए) के अंतर्गत आता है, इसलिए इस मुद्दे पर आगे किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, अफीम डेरिवेटिव को प्रविष्टि 93 के तहत निपटाया जाना है, इसलिए धारा 2 (xv) के खंड (ए) के तहत आने वाली शुद्ध अफीम के मामले में, मॉर्फिन की मात्रा का निर्धारण आवश्यक नहीं है। प्रविष्टि 92 विशेष रूप से लागू है यह सुनिश्चित करने के लिए कि अफ़ीम की मात्रा छोटी मात्रा या व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आती है या नहीं।"

26. उक्त मामले में, ई. माइकल राज (सुप्रा) में संदर्भित निर्णय को इस प्रकार बताते हुए अलग किया गया था: -

"ई. माइकल राज के मामले में निर्णय हेरोइन यानी डायसेटाइलमॉर्फिन से संबंधित है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 (xvi) में परिभाषित शब्द के अर्थ के भीतर एक "अफीम व्युत्पन्न" है और इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2(xi)(ए) के अर्थ के अंदर एक "निर्मित औषधि" है। इस प्रकार उक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं है।"

अंततः, अनुच्छेद 25 में न्यायालय ने इस प्रकार कहा:-

"यहां लागू अधिसूचना प्रत्येक प्रतिबंधित सामग्री के लिए विभिन्न मादक औषधियों और मनोदैहिक पदार्थों की छोटी और व्यावसायिक मात्रा को निर्दिष्ट करती है। प्रविष्टि 56 हेरोइन से संबंधित है, प्रविष्टि 77 मॉर्फिन से संबंधित है, प्रविष्टि 92 अफीम से संबंधित है, प्रविष्टि 93 अफीम व्युत्पन्न आदि से संबंधित है, इत्यादि। इसलिए, अधिसूचना न केवल अफ़ीम और मॉर्फ़ीन के बीच, बल्कि अफ़ीम और अफ़ीम व्युत्पन्न के बीच भी अंतर करती है। निस्संदेह, मॉर्फ़ीन अफ़ीम के डेरिवेटिव में से एक है। इस प्रकार, कानून के तहत आवश्यकता सबसे पहले पहचानने और वर्गीकृत करने की है बरामद पदार्थ और फिर यह पता लगाना कि किस प्रविष्टि के तहत इससे निपटना आवश्यक है। यदि यह धारा 2(xv) के खंड (ए) में परिभाषित अफीम है तो मॉर्फिन सामग्री का प्रतिशत पूरी तरह से अप्रासंगिक होगा। यह केवल है यदि आपत्तिजनक पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2(xv) के खंड (बी) में निर्दिष्ट मिश्रण के रूप में पाया जाता है, तो मॉर्फिन सामग्री की मात्रा प्रासंगिक हो जाती है।"

27. एक और पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 28 में पाया कि जब्त वस्तु में 50 ग्राम से अधिक टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल था दोनों आरोपी व्यक्तियों के संबंध में। प्रतिबंधित सामग्री, अर्थात् टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल (टीएचसी) की वाणिज्यिक मात्रा, जैसा कि प्रविष्टि संख्या 150 में बताया गया है 50 ग्राम है। यदि मान भी लिया जाए कि उक्त प्रतिशत जब्त वस्तु में पाया जाता है तो भी प्रतिबंधित वस्तु "मध्यवर्ती" मात्रा से आगे निकल जाएगी और "वाणिज्यिक" मात्रा के अंतर्गत आ जाएगी।

किसी भी आधार पर निर्णय लेने पर, हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण सही है। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं और मानते हैं कि जब्त की गई वस्तु वाणिज्यिक मात्रा के अंतर्गत आती है और इसलिए धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई सज़ा बिल्कुल त्रुटिहीन है।

28. यदि हम प्रतिवादी-अभियुक्तों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत एक अन्य निवेदन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपने कर्तव्य में असफल होंगे। उनका कहना है कि आरोपी व्यक्ति पहले ही सात साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें दोबारा जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। धारा 20 (बी) (ii) (सी) में कहा गया है कि न्यूनतम सज़ा दस साल होगी जिसे बीस साल तक बढ़ाया जा सकता है और लगाया जाने वाला न्यूनतम जुर्माना एक लाख रुपये है जो दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। प्रावधान डिफ़ॉल्ट खंड के बारे में भी प्रदान करता है जो न्यायालय द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। जब न्यूनतम सज़ा निर्धारित है तो कोई भी अदालत कम सज़ा नहीं दे सकती। नरेंद्र चंपकलाल त्रिवेदी बनाम गुजरात राज्य (2012) 7 एससीसी 80, में जब एक दलील दी गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय निर्धारित सज़ा से कम सज़ा दे सकता है, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि: -

> "...जहां न्यूनतम सज़ा प्रदान की जाती है, हमें लगता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा तथाकथित कम करने वाले कारकों के आधार पर सज़ा कम करनी होगी क्योंकि यह वैधानिक जनादेश को प्रतिस्थापित करने के समान होगा और इसके अलावा यह मूल वैधानिक प्रावधान की

अनदेखी करने जैसा होगा जो एक आपराधिक कृत्य के लिए न्यूनतम सज़ा निर्धारित करता है..."

29. एक बार फिर, मध्य प्रदेश राज्य बनाम अयूब खान (2012) 8 एससीसी 676 में, जहां उच्च न्यायालय ने कम सज़ा सुनाई थी, इस न्यायालय ने कानून की स्थिति का विश्लेषण करते हुए इस प्रकार राय दी है: -

"विधानमंडल ने अपने विवेक से कुछ अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सज़ा तय की है - हथियार और गोला-बारूद रखना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए सज़ा तीन साल से कम नहीं होगी। विधायिका ने अपने विवेक से महसूस किया कि ऐसा होना चाहिए ऐसे अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सज़ा होनी चाहिए, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब हम आतंकवाद और अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के खतरे का सामना कर रहे हों, हथियारों और गोला-बारूद तक अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए और अधिक कठोर सज़ा का प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के दो राउंड गोलियों और 50 ग्राम विस्फोटक के साथ देश निर्मित बंदूक के कब्जे में पाया जाता है, इसके विपरीत सबूत के अभाव में यह माना जाना चाहिए कि अवसर आने पर इसका उपयोग करने के इरादे से इसे ले जाया जा रहा है बड़े पैमाने पर लोगों के लिए हानिकारक हो। संभवतः, राष्ट्रीय हित और साथी नागरिकों की सुरक्षा सहित उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विधायिका ने अपने विवेक से न्यूनतम अनिवार्य सज़ा निर्धारित की है। एक बार जब अभियुक्त को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) के

तहत किए गए अपराध के लिए दोषी पाया गया, तो उसे आवश्यक रूप सेक़ानून के तहत निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य सज़ा भुगतनी होगी।"

30. उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, हम उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को कायम रखने में असमर्थ हैं और तदनुसार, उसे अस्थिर करते हैं और पाते हैं कि आरोपी-प्रतिवादी, मुश्ताक अहमद और गुलज़ार अहमद, धारा के तहत दंडनीय अपराध के दोषी हैं। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) और उनमें से प्रत्येक को दस साल के कठोर कारावास और रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई है। 1 लाख रुपये और जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा।

31. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है और आपराधिक अपील संख्या 35 और 36 /2009 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और जहां तक सज़ा का सवाल है, विद्वान विचारण न्यायाधीश के फैसले को संशोधित किया जाता है।

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।